

हरियाणा सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 अगस्त, 2004

संख्या 1/3/17/02/एस० ओ० -I/पेंशन.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, पंजाब सिविल सेवाएं नियम, जिल्द -II, हरियाणा राज्यार्थ को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम पंजाब सिविल सेवाएं, जिल्द -II, (हरियाणा द्वितीय संशोधन) नियम, 2004, कहे जा सकते हैं।

1-क. ये तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

2. पंजाब सिविल सेवाएं नियम, जिल्द -II में, परिशिष्ट-I में पारिवारिक पेंशन स्कीम, 1964 में, पैरा 4 में, उप-पैरा (ii) तथा (iii) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरे प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“(ii) इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए परिवार में अधिकारी के निम्नलिखित रिश्तेदार शामिल हैं :—

(क) पत्नी, पुरुष अधिकारी के दशा में ;

(ख) पति, महिला अधिकारी के दशा में ;

(ग) अवयस्क पुत्र ;

(घ) अविवाहित/ अवयस्क पुत्रियां ;

(ङ) विधवा/विधिपूर्वक तलाकशुदा पुत्रियां ; तथा

(छ) अविवाहित अधिकारी के माता-पिता।

टिप्पण 1. खण्ड (ग) व (घ) में सेवानिवृत्ति से पहले विधिपूर्वक गोद लिए गए बालक शामिल हैं।

टिप्पण 2. खण्ड रूप से अलग हुए पत्नी/पति सरकारी कर्मचारी की पत्नी/पति होने की अपनी/अपना कानूनी हैसियत से वंचित नहीं होंगे और इसलिए वे पारिवारिक पेंशन स्कीम, 1964, के लाभ के लिए पात्र हैं।

(iii) पेंशन के लिए निम्नलिखित स्वीकार्य है :—

(क) विधवा/विदुर की दशा में मृत्यु या पुनः शादी की तिथि तक, जो भी पहले हो ;

(ख) पुत्र/अविवाहित पुत्री जिसमें विधवा/तलाकशुदा पुत्री भी शामिल है, की दशा में जब तक वे 25 साल की आयु पूरी नहीं कर लेते ; और

(ग) ऐसे माता-पिता की दशा में जो सरकारी कर्मचारी पर पूर्ण रूप से आश्रित थे जब वह जीवित था, को मृत्यु की तिथि तक बशर्त मृतक कर्मचारी अपने पीछे न तो विधवा और न ही बालक छोड़ गया था।

परन्तुक अविवाहित पुत्री सहित विधवा/तलाकशुदा पुत्री अपनी शादी/पुनः शादी की तिथि से पेंशन के लिए अपात्र होगी।

परन्तुक यह और कि पुत्र/अविवाहित पुत्री सहित विधवा/तलाकशुदा पुत्री, यदि वह अपनी जीविका कमाना शुरू कर देता है/देती है, पेंशन के लिए अपात्र हो जाएगा/जाएगी ;

माता-पिता और विधवा/तलाकशुदा पुत्री के सम्बन्ध में आय का मानदण्ड यह होगा कि उनकी आमदनी प्रति मास 2550/- रुपये से अधिक नहीं है। परन्तु माता-पिता और विधवा/तलाकशुदा पुत्री को भी इस आशय का एक वार्षिक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनकी आमदनी प्रति मास 2550/- रुपये से अधिक नहीं है। पारिवारिक पेंशन के लिए ऊपरी सीमा, मृतक कर्मचारी के मूल वेतन का 30 प्रतिशत जो प्रतिमास कम से कम 1913/-रुपए होगी।

टिप्पण: (i) जहां अधिकारी की एक से अधिक विधवा जीवित हैं, उनको पेंशन बराबर हिस्से में भुगतान की जाएगी। विधवा की मृत्यु पर, पेंशन का उसका हिस्सा उसके पात्र अवयस्क बालक को भुगतानयोग्य होगा। यदि अपनी मृत्यु के समय पर, विधवा कोई भी पात्र अवयस्क बालक नहीं छोड़ती है, तो पेंशन के उसके हिस्से का भुगतान समाप्त हो जाएगा।

(ii) जहां अधिकारी की विधवा जीवित है किन्तु अन्य पत्नी से पात्र अवयस्क बालक को छोड़ गया है, पात्र अवयस्क बालक को पेंशन के उस हिस्से का जो उसकी माता यदि वह अधिकारी की मृत्यु के समय पर जीवित होती तो प्राप्त कर रही होती का भुगतान किया जाएगा।

भास्कर चटर्जी,

वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
वित्त विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

FINANCE DEPARTMENT

Notification

The 26th August, 2004

No. 1/3/17/02/SO-I/Pension.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the constitution of India and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Punjab Civil Services Rules, Volume II, in its application to the State of Haryana, namely :—

1. These rules may be called the Punjab Civil Services, Volume-II (Haryana Second Amendment) Rules, 2004.

1-A. They shall come into force with immediate effect.

2. In the Punjab Civil Services Rules, Volume-II, in Appendix 1, in Family Pension Scheme, 1964, in para 4, for sub-paras (ii) and (iii) the following sub-paras shall be substituted, namely :—

“(ii) “Family” for the purposes of this scheme includes the following relatives of the officer :—

- (a) wife, in the case of a male officer;
- (b) husband, in the case of a female officer;
- (c) minor sons;
- (d) unmarried minor daughters;
- (e) widowed/legally divorced daughters; and
- (f) the parents of an unmarried officer.

Note 1.—Clauses (c) and (d) include children adopted legally before retirement.

Note 2.—A judicially separated wife/husband does not lose her/his legal status of wife/husband of the Government employee and is thus eligible for the benefit of the Family Pension Scheme, 1964.

(iii) The pension is admissible :—

- (a) in the case of widow/widower up to the date of death or remarriage, whichever is earlier;
- (b) in the case of son/unmarried daughter including widowed/divorced daughter until he/she attains the age of 25 years; and
- (c) in the case of parents who were wholly dependent on the Government employee when he/she was alive, up to the date of death provided the deceased employee had left behind neither a widow nor a child.

Provided that an unmarried daughter including widowed/divorced daughter will become ineligible for pension from the date of her marriage/remarriage.

Provided further that the son/unmarried daughter including widowed/divorced daughter shall become ineligible for pension if he or she starts earning livelihood.

The income criteria in respect of parents and widowed/divorced daughter will be that their earning is not more than Rs. 2550/- per month. Provided also that parents and widowed/divorced daughter shall produce an annual certificate to the effect that their earning is not more than Rs. 2550/- per month. The upper ceiling of family pension will be 30% of basic pay of the deceased employee, subject to a minimum of Rs. 1913/- per month.

Note : (i) Where an officer is survived by more than one widow, the pension will be paid to them in equal shares. On the death of a widow, her share of the pension will become payable to her eligible minor child. If at the time of her death, a widow leaves no eligible minor child, the payment of her share of the pension will cease.

(ii) Where an officer is survived by a widow but has left behind an eligible minor child from another wife, the eligible minor child will be paid the share of pension which the mother would have received, if she had been alive at the time of the death of the officer.

BHASKAR CHATTERJEE,

Financial Commissioner and Principal Secretary to
Government Haryana, Finance Department.